अध्याय 22

अधिमांग एवं न्यून मांग अवधारणा
(Concept of Excess Demand and deficient Demand)

पिछले अध्याय में हम कीन्स द्वारा प्रतिपादित आय निर्धारण के सिद्धान्त का अध्ययन कर चुके हैं। कीन्स ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विचारों की कटु आलोचना की है।

इस पाठ के अध्ययन करने से पूर्व हमें प्रतिष्ठित और केन्जीय विचारधारा की प्रमुख विचारों से परिचित होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार आय का उत्पादन निर्धारण वास्तविक घटकों जैसे पूँजी स्टॉक, श्रम की पूर्ति द्वारा प्रभावित होता था। सामान्य कीमत स्तर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके अनुसार सामान्य कीमत मुद्रा की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती थी।

कीन्स के विचारों का प्रार्दुभाव सन् 1930 की व्यापक आर्थिक मन्दी के समय हुआ। कीन्स के अनुसार आय और उत्पादन के निर्धारण का सिद्धान्त कीमत स्तर को स्थिर मानकर चलता है। इनके अनुसार आय का निर्धारण उस बिन्दु पर होता है जहाँ समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है। कीन्स ने मन्दी में फैली व्यापक बेरोजगारी और अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का प्रमुख कारण प्रभावपूर्ण मांग की कमी को बताया था।

समग्र मांग (AD) समग्र पूर्ति (AS) मॉडल द्वारा सामान्य कीमत स्तर का निर्धारण तथा उत्पादन में होने वाले उतार चढ़ाव का पता चलता है। उसके आधार पर मौद्रिक एवं राजकोषीय उपायों को सरकार द्वारा अपनाया जाता है। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या है। इसलिए पहले इन दोनों अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। आइये इन अवधारणाओं को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं।

समग्र मांग **(AD) –**

समग्र मांग में उपभोग व्यय, निजी विनियोग व्यय, सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं का क्रय और शुद्ध निर्यात शामिल होते हैं। (Y=C+I+G+Xn) अन्य बातों के समान रहने पर विभिन्न कीमत स्तर पर जो उपभोक्ताओं, विनियोगकर्त्ताओं सरकार और विदेशियों द्वारा वस्तु और सेवाएँ खरीदी जाती हैं उसे समग्र मांग कहते हैं।

समग्र मांग के अवयव समीकरण के रूप में इस प्रकार व्यक्त किए जा सकते हैं–

$Y = C+I+G+Xn$

जहाँ

C = उपभोग व्यय

I = विनियोग व्यय

G = सरकारी व्यय

Xn = X-M जहाँ X = कुल निर्यात, M = कुल आयात

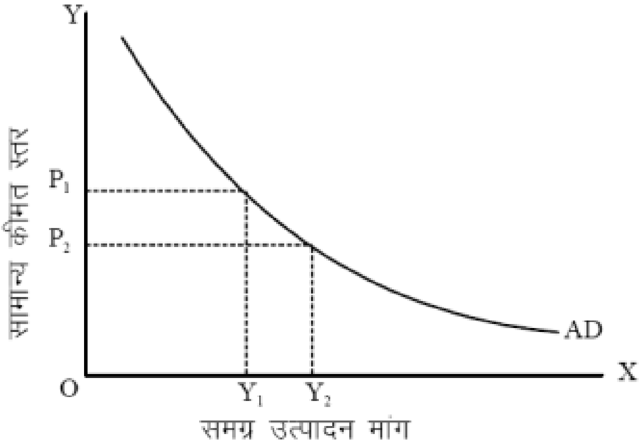

रेखाचित्र 22.1

चित्र द्वारा समग्र मांग वक्र को दर्शाया गया है। x अक्ष पर समग्र उत्पादन मांग और Y अक्ष पर सामान्य कीमत स्तर है। यह वक्र समग्र वस्तु और सेवाओं की मांग और सामान्य कीमत स्तर में सम्बन्ध को बताता है। प्रारम्भिक कीमत OP_1 और उत्पादन OY_1 हैं। यदि कीमतें बढ़कर OP_1 से OP_2 होती है, तो इसके तीन प्रभाव पड़ते हैं :–

1- कीमत बढ़ने पर उपभोग व्यय घट जाता है।

2- कीमत बढ़ने पर लोगों को लेन–देन उद्देश्य से अधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है, जिससे ब्याज दर बढ़ती है, परिणामस्वरुप विनियोग की मांग घट जाती है।

3- कीमत बढ़ने पर आयात अधिक व निर्यात कम होते हैं,

जिससे शुद्ध निर्यात (X-M) की मात्रा कम हो जाती है, इस प्रकार कीमत में वृद्धि होने पर समग्र मांग कम हो जाती है। चित्र 22.1 के अनुसार समग्र उत्पादन मांग OY_2 से घटकर OY_1 हो जाती है। इसके विपरीत कीमत घटने पर समग्र उत्पादन की मांग बढ़ जाती है।

समग्र मांग वक्र की व्युत्पत्ति –

समग्र मांग को कीन्स के आय निर्धारण चित्र A के द्वारा व्युत्पत्ति कर सकते हैं।

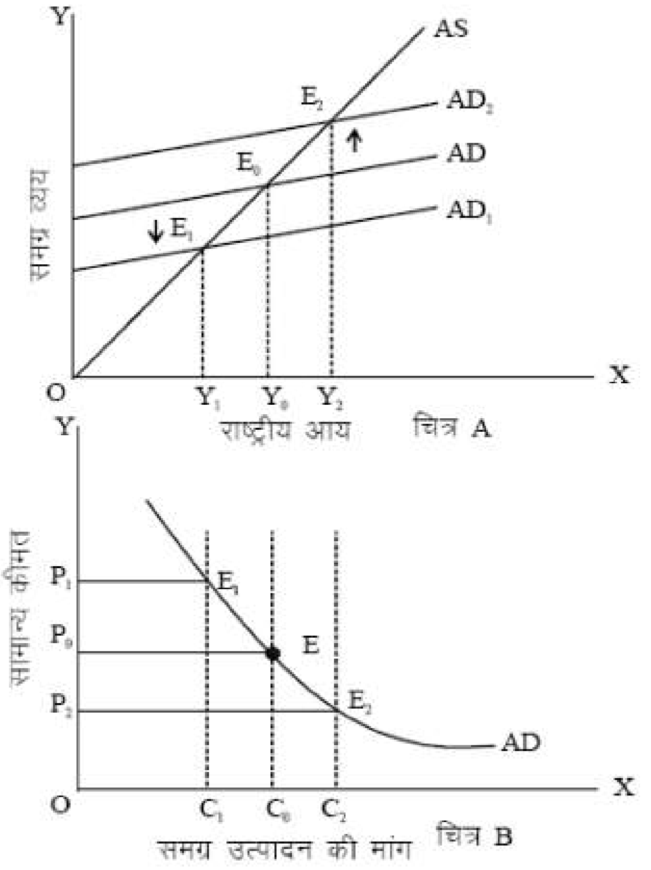

रेखाचित्र 22.2

चित्र A में कीन्स द्वारा समग्र व्यय (नियोजित व्यय) को विभिन्न राष्ट्रीय आय स्तर (GNP) पर बताया गया है, जबकि चित्र B में व्युत्पन्न समग्र मांग विभिन्न कीमत स्तरों पर दर्शाई गई है।

प्रारम्भिक साम्य में समग्र मांग, समग्र पूर्ति (45° रेखा) को E_0 पर काटती है। जहाँ आय Y_0 निर्धारित होती है। खण्ड B में Y_0 आय के स्तर पर समग्र मांग C_0 और सामान्य कीमत स्तर P_0 है। इसी प्रकार यदि सामान्य कीमत स्तर पर P_2 हो जाती है तो लोगों की क्रय शक्ति बढ़ने पर उपभोग व्यय AD से AD_2 ऊपर की ओर खिसक जाता है। साम्य AD_2=AS (45° रेखा) E_2 पर आय Y_2 होती है। समग्र मांग OC_2 होता है। इस प्रकार कम कीमत पर समग्र उत्पादन मांग अधिक होती है इसके विपरीत बढ़ी हुई कीमत पर साम्य E_1 बिंदु पर प्राप्त होगा जहाँ AS=AD_1 आय Y_1 होती है और समग्र मांग OC_1 घट जाती है। इस प्रकार सामान्य कीमत स्तर और समग्र उत्पादन की मांग में विपरीत सम्बन्ध पाया जाता है, जो चित्र B में AD वक्र से स्पष्ट होता है।

समग्र पूर्ति **(AS)** –

अन्य बातें समान रहने पर विभिन्न सम्भव कीमतों पर फर्में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना चाहती है, समग्र पूर्ति कहलाती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सिद्धान्त पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। अतः पूर्ण रोजगार की स्थिति में समग्र पूर्ति वक्र एक लम्बवत रेखा होती है, जो निम्न चित्र 22.3 द्वारा दर्शायी जाती है। यहाँ AS पूर्णतया बेलोचदार है।

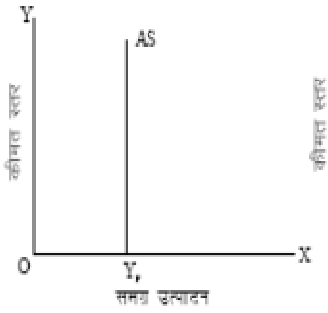

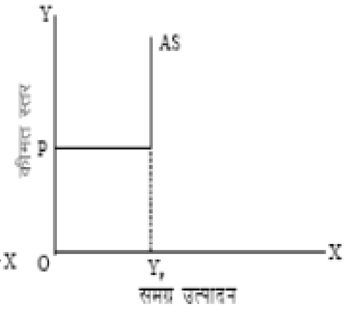

रेखाचित्र 22.3 **रेखाचित्र 22.4**

इसके विपरीत कीन्स के अनुसार समग्र पूर्ति वक्र मन्दी के समय प्रारम्भ में क्षैतिज होता है फिर पूर्ण रोजगार बिन्दु पर लम्बवत् होता है। चित्र 22.4 में दर्शाया गया है। क्षैतिज क्षेत्र में समग्र मांग में वृद्धि होने पर उत्पादन में वृद्धि होती है एवं कीमतें अपरिवर्तित रहती हैं, जबकि लम्बवत् समग्र पूर्ति वक्र अर्थात् पूर्ण रोजगार पर समग्र मांग में वृद्धि होने पर उत्पादन में वृद्धि नहीं होती अपितु कीमतों में वृद्धि होती है।

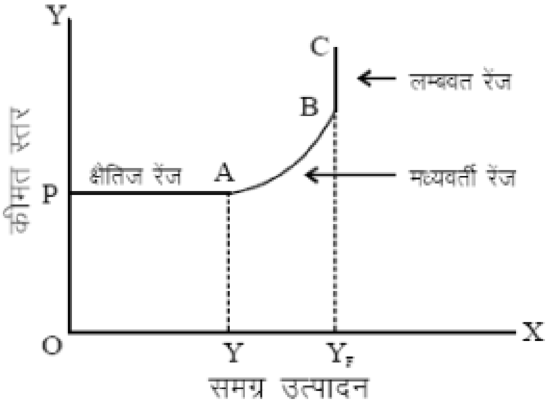

रेखाचित्र 22.5

चित्र 22.5 में क्षैतिज रेंज (PA) केन्जीयन रेंज कहलाती है, अप्रयुक्त साधनों के उपयोग से प्रति इकाई उत्पादन लागत में वृद्धि नहीं होने पर कीमतों में भी वृद्धि नहीं होती है। इस रेंज में केवल उत्पादन में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति को वक्र के PA भाग में व्यक्त किया गया है।

मध्यवर्ती रेंज में (Y और Y_F मध्य) समग्र मांग में वृद्धि कीमतों में भी वृद्धि करती है। पूर्ण रोजगार पूर्व उत्पादन बढ़ाने पर प्रति इकाई लागत भी बढ़ती है जिससे कीमतों में भी वृद्धि होती है।

लम्बवत् रेंज (BC) पूर्ति वक्र पूर्णतया बेलोचदार होता है, जो कि उत्पादन को पूर्ण रोजगार स्तर को दर्शाता है। इसे प्रतिष्ठित रेंज भी कहते हैं। यहाँ कीमतों में परिवर्तन होता है एवं उत्पादन मात्रा अपरिवर्तित रहती है क्योंकि साधनों का पूर्ण क्षमता तक उपयोग हो चुका होता है।

समष्टि आर्थिक साम्य –

समग्र मांग व पूर्ति की आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् हम समष्टि आर्थिक साम्य को AD-AS मॉडल द्वारा समझने का प्रयास करते हैं।

अल्पकालीन संतुलन अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को बताता है। वास्तविक GDP, सामर्थ्य (Potential GDP) के इर्द–गिर्द रहती है। मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति किस प्रकार कारगर सिद्ध होती है, यह AD-AS मॉडल द्वारा बताया गया है।

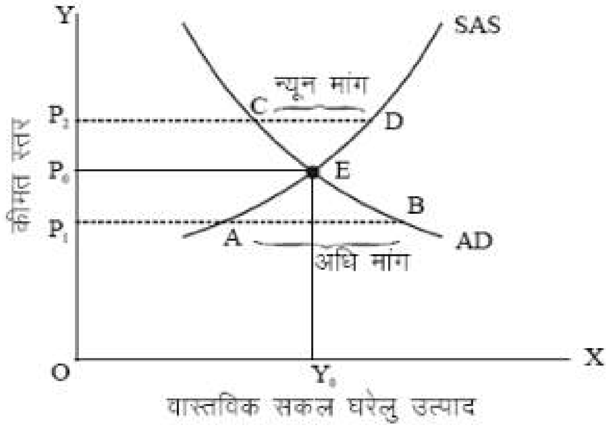

रेखाचित्र 22.6

समग्र मांग (AD) अल्पकालीन पूर्ति वक्र (SAS) के बराबर होने पर साम्य E पर होता है। जहाँ आय OY_0 और कीमत स्तर P_0 निर्धारित होता है। यदि कीमत P_2 होती है तो समग्र पूर्ति, समग्र मांग से अपेक्षाकृत अधिक होती है (CD) जिसे न्यून मांग कहते हैं। ऐसी स्थिति में उत्पादक उत्पादन में कमी करता है। मांग कम होने पर वह उत्पादित माल को बेच नहीं पाता है, अतः उसके पास तैयार माल स्टॉक के रुप में जमा होता जाता है। कीमत क्रमशः कम होने लगती है और पुनः P_0 साम्य कीमत को प्राप्त करती है।

इसके विपरीत यदि कीमतें OP_1 होती है तो समग्र मांग, समग्र पूर्ति की अपेक्षाकृत अधिक होती है, (AB) जिसे आधिक्य मांग कहा जाता है। अधिक मांग उत्पादक को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करती है। उत्पादक द्वारा उत्पादन साधनों की मांग बढ़ने पर साधन लागत में वृद्धि होती है। अन्ततः वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगती है और पुनः साम्य P_0 कीमतों पर स्थापित होता है।

अल्पकाल में मौद्रिक मजदूरी दर स्थिर होती है। वास्तविक GDP पर साम्य सामर्थ्य GDP से कम या अधिक हो सकता है।

दीर्घकाल में साम्य तब होता है, जब समग्र मांग, दीर्घकालीन समग्र पूर्ति वक्र के बराबर होता है। दीर्घकालीन पूर्ति वक्र GDP लम्बवत होने पर सामर्थ्य GDP के बराबर होता है। दीर्घकाल में वास्तविक GDP, सामर्थ्य GDP के बराबर होती है।

मन्दी–

जब आर्थिक क्रियाएँ जैसे वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, रोजगार, आय, मांग तथा कीमतों में पर्याप्त कमी होती है।

समृद्धि–

कीमतों में स्फीतिकारी वृद्धि होती है। उत्पादन, रोजगार और आय ऊँचे स्तर पर होते हैं। वस्तु और सेवाओं की मांग अधिक होती है।

मौद्रिक और राजकोषीय नीति –

ऊपर किये गये विवेचन से स्पष्ट होता है कि मन्दी में न्यून मांग की समस्या उत्पन्न हो जाती है अर्थात् समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम होती है। ऐसी परिस्थिति में सरकार उचित राजकोषीय नीति अपनाती है। सरकार सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके मांग में वृद्धि के प्रयास करती है। सार्वजनिक व्यय जैसे सड़क बनवाना, बाँध निर्माण, स्कूलों व अस्पतालों जैसे भवनों का निर्माण आदि जिससे रोजगार, आय और मांग का सृजन होता है। इसी के साथ करों में कमी उपभोक्ताओं के व्यय योग्य आय में वृद्धि करती है। यह प्रयास तभी कारगर होता है जब सरकार करों में कोई वृद्धि नहीं करती है। इसी तरह मौद्रिक नीति में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की जाती है जिसके परिणामस्वरुप ब्याज की दर में कमी होती है। निजी विनियोग में वृद्धि होती है। जिसमें समग्र मांग में वृद्धि होती है। इस उद्देश्य हेतु बैंक दर में कमी, खुले बाजार में केन्द्रीय बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय, तरल नकद कोषानुपातों में

कमी की जाती है। निष्कर्ष रुप में कहा जा सकता है कि न्यून मांग में सरकार विस्तारक (Expansionary) मौद्रिक और राजकोषीय नीति अपनाती है। मन्दी में दोनों नीतियों की तुलना करने पर राजकोषीय नीति अधिक सफल होती है। न्यून मांग (मन्दी) के समय व्यवसायियों के पास पहले ही बहुत स्टॉक इक्ट्ठा होता है जिसे वह बेच नहीं पाते। इसलिए ब्याज दर कम होने पर भी विनियोग हेतु प्रेरित नहीं होते। उपभोक्ता वर्ग भी बेरोजगारी और निम्न आय के कारण टिकाऊ वस्तु हेतु ऋण नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए मौद्रिक नीति अधिक सफल नहीं होती है।

राजकोषीय नीति –

इस नीति द्वारा सरकार द्वारा कर और व्यय में परिवर्तन द्वारा पूर्ण रोजगार और कीमत स्तर में स्थिरता लाने का प्रयास किया जाता है।

मौद्रिक नीति –

केन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने और आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है।

इसके विपरीत मांग आधिक्य में मुद्रा स्फीति के समय सरकार द्वारा संकुचित मौद्रिक और राजकोषीय नीति अपनाई जानी चाहिए। राजकोषीय नीति के तहत् सरकार को करों में वृद्धि, अनावश्यक व्यय में कटौती करके समग्र मांग में कमी की जानी चाहिए। करो की दरों में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए अन्यथा निवेश और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सरकार द्वारा अनिवार्य बचत स्कीम भी चलायी जा सकती है। सरकार को अतिरेक बजट बनाने का प्रयास करना चाहिए एवं सार्वजनिक ऋणों के पुनः भुगतान को रोक देना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में कठोर मौद्रिक नीति अपनाई जानी चाहिए। आधिक्य मांग के कारण कीमतों में वृद्धि को रोकने हेतु केन्द्रीय बैंक, बैंक–दर में वृद्धि, खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय और रिजर्व अनुपात में वृद्धि करता है। साथ ही चयनात्मक साख नियंत्रण जैसे साख सीमा आवश्यकता को बढ़ाता है। साथ ही उपभोक्ता साख को भी नियंत्रित करता है। इन सभी उपायों के अतिरिक्त करेन्सी का विमुद्रीकरण भी किया जा सकता है। इस प्रकार न्यून और आधिक्य मांग की स्थिति में राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के उचित उपायों के सामंजस्य से उभरा जा सकता है।

विमुद्रीकरण –

जब देश की सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है। 8 नवम्बर 2016 को हाल ही में सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोटों को उसी रात 12 बजे से बंद किए जाने की घोषणा की है।

महत्वपूर्ण बिन्दु

1- समग्र मांग में उपभोग व्यय, विनियोग व्यय, सरकारी व्यय और शुद्ध निर्यात शामिल है– $AD=C+I+G+X_n$

2- समग्र मांग विभिन्न कीमत स्तर पर कुल वस्तु और सेवाओं की मांगी गई मात्रा को व्यक्त करता है।

3- समग्र मांग और सामान्य कीमत स्तर में विपरीत सम्बन्ध होता है।

4- समग्र पूर्ति प्रत्येक सम्भावित कीमत पर फर्मों के कुल वस्तु और सेवाओं के उत्पादन को दर्शाता है।

5- जहाँ समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है वहाँ कीमत स्तर और समग्र उत्पादन का निर्धारण होता है।

6- न्यून मांग से अर्थ है जब समग्र मांग, समग्र पूर्ति से कम होती है।

7- आधिक्य मांग का अर्थ जब समग्र पूर्ति, समग्र मांग से कम होती है अथवा समग्र मांग की मात्रा समग्र पूर्ति से अधिक होती है।

8- न्यून मांग मन्दी की स्थिति बताती है।

9- आधिक्य मांग मुद्रा स्फीति की स्थिति बताती है।

10- मन्दी में विस्तारक मौद्रिक और राजकोषीय नीति कारगर होती है।

11- मांग आधिक्य (मुद्रा स्फीति) में संकुचित मौद्रिक और राजकोषीय नीति अपनाने पर समग्र मांग में कमी होती है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न–

1- न्यून मांग होती है जब –

(अ) AD<AS (ब) AD>AS

(स) AD=AS (द) AD#AS

2- समग्र मांग होती है –

(अ) उपभोग और विनियोग व्यय

(ब) सरकारी व्यय

(स) शुद्ध निर्यात

(द) उपरोक्त सभी

3- मन्दी में राजकोषीय नीति के तहत् उपाय है –

(अ) करों में वृद्धि

(ब) सार्वजनिक व्यय में वृद्धि

(स) सार्वजनिक व्यय में कमी

(द) कीमतों में वृद्धि

4- मुद्रा स्फीति को रोकने हेतु मौद्रिक नीति के तहत उठाया जाने वाला कदम है –

(अ) बैंक दर में वृद्धि
(ब) करों में कमी
(स) सार्वजनिक व्यय में वृद्धि
(द) बैंक दरों में कमी

5- चित्र में समग्र पूर्ति वक्र किसके अनुसार होता है –

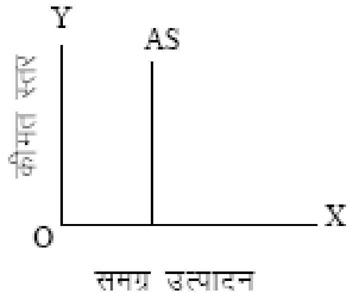

(अ) केन्जीय (ब) प्रतिष्ठित
(स) मौद्रिकवाद (द) रेटेक्स

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न–

1- समग्र मांग का अर्थ बताइये।

2- समग्र मांग के चार अवयव लिखिए।

3- समग्र पूर्ति का अर्थ बताइये।

4- समष्टि आर्थिक साम्य का क्या अर्थ है?

5- मन्दी का अर्थ बताइये।

लघूत्तरात्मक प्रश्न–

1- न्यून मांग को समझाइये।

2- आधिक्य मांग से क्या तात्पर्य है?

3- मौद्रिक नीति से क्या अभिप्राय है?

4- राजकोषीय नीति के क्या उपकरण है?

5- मुद्रा स्फीति में मौद्रिक नीति के क्या उपाय अपनाये जाते है?

निबन्धात्मक प्रश्न–

1- AD और AS मॉडल की विस्तार से व्याख्या कीजिए।

2- प्रतिष्ठित और कीन्स के पूर्ति वक्र में चित्र की सहायता से भेद कीजिए।

3- मन्दी में राजकोषीय नीति को कैसे प्रभावी रुप से उपयोग में लिया जा सकता है?

4- मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये जा सकने वाले चार उपाय लिखिए।

उत्तर तालिका

1	2	3	4	5
अ	द	ब	अ	ब